International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709; Print ISSN: 2664-8695
Received: 02-11-2018; Accepted: 04-12-2018; Published: 04-01-2019
Volume 1; Issue 1; 2019; Page No. 04-07

धान आधिक्य व्यवस्था- एक उपयोगी, पर्यावरण हितैषी रोपण प्रक्रिया व ज्ञान की राजनीति

Ajay Kumar
Knowledge, Development and Politics, Conceptual and Field Issues, Hyderabad, India

Introduction

एसआरआइ, धन आधिक्य व्यवस्था जो धान उगाहने की एक स्थानीय ज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है जिसमें कम लागत, श्रम, भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के साथ उत्पादन किया जाता है| इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम आरंभ मडागास्कर में फ्र. हेनरी डे लओलेन के द्वारा वहाँ की वर्तमान दुर्दशा के प्रतिउत्तर में किया जिसनें लोगों को वहाँ काफ़ी लाभ प्रदान किया| आगे दशकों में इसका विस्तार अन्य देशों में भी हुआ और इस पद्दति का सस्ता होना, कम लागत, अधिक निर्गत, आसान समझ व पर्यावरण हितैषी होने के कारण कई देशों द्वारा इसे अपनाया गया परंतु इसके साथ ही कई जगह अपनी पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने या बाज़ारवादियों के प्रभाव के कारण इसका विस्तार नहीं हो पाया| हालाँकि 50 से अधिक देशों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है परंतु अभी भी यह उतना व्यापक नहीं हो पाया है जिसके पीछे अनेक प्रभावकारी तत्व हैं जिनमें सबसे प्रमुख राज्य, पूंजीपती व बाज़ारी ताकतें है जो इस प्रकार के ज्ञान को पहचान नहीं बनानें देतीं हैं और इस प्रकार की स्थानीय आवाज़ों को दबा दिया जाता है, इन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा इस लेख में समझानें का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से यह पूरा प्रक्रम कार्य करता है, जो एक ज्ञान की राजनीति के पहलू को सामने लाता है|

फ्र. हेनरी डे लओलेन(Fr. Henri De Laulanie) इसके द्वारा ग्रेगर मेनडेल(Gregor Mendel) की परंपरा को आगे बढ़ाया जिनके द्वारा विज्ञान में जेनिटिक को लाने का कार्य किया गया था| एसआरआइ की खोज के परिदृश्य में लओलेन का तदर्थ उद्देश्य विद्यमान ग़रीबी व कृषक समस्या का समाधान करना था, कृषकों को स्वाभिलंभ बनाना था क्योंकि उनकी स्थिति भी उन्हें इस प्रकार की कीमती तकनीकी को मोहैय्या करा सकने की अनुमति नहीं देती थी, इसी कारण इस प्रकार के उत्पादन किया गया जिसे नागरिक समाज का उत्पादन भी माना जाता था|[1] वर्तमान समय में स्थानीय खोजों को कुछ हद तक पहचान प्राप्त हो रही है, एसआरआइ इसी प्रकार का एक आंदोलन था जिसने स्थानीय ज्ञान को महत्व प्रदान किया व कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाया[2] कई वैज्ञानिक इसे तकनीकी परिवर्तन की जगह पद्दतिय परिवर्तन नाम देना ज़्यादा स्वीकृत समझते है|[3] एसआरआइ एक बहुआयामी लाभकारी प्रक्रम है जिसमें श्रम की बचत, 25-50% पानी की बचत, बीज़ बचत, उत्पादन के निर्गत में 25-50% की वृद्धि तक प्राप्ति होती है|[4]

एसआरआइ प्रक्रिया को विस्तरित करने में इंटरनेट जैसी व्यवस्थाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है[5] 1999 तक यह व्यवस्था पूरे विश्व के लिए अनजान थी, कर्नेल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुड एग्रीकल्चर एंड डेवेलपमेंट(CIIFAD) व इसके निदेशक अपोफ्फ(Uphoff) ने इस खोज़ को मुक्त रूप से अन्य जगहों तक पहुँचाया व कृषकों, शोधकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया| एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान समय में 50 देशों में एक करोड़ कृषकों व 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका इस्तेमाल किया जाता है[6] इसी प्रक्रम व इसकी सफलता ने 2004 को अंतराष्ट्रीय धान वर्ष घोषित किया गया जिसने 'धान युद्ध' व विज्ञान के साथ इसका विवाद आरंभ किया|[7]

हालाँकि कई कृषकों ने इस अपनी पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था के साथ परिवर्तन को नहीं अपनाया| इस प्रकार के उत्पादन को अन्य नई तकनीकीयों से अलग बताया जाता है क्योंकि यह नागरिक समाज के द्वारा प्रदान की गयी है, किसी शोध संस्था या प्रयोगशाला से इसका उत्थान नहीं हुआ है बल्कि इस पद्दति का आगमन कृषकों, गैर-सरकारी संगठनों व राज्योत्तर अभिनेताओं के प्रयासों से संभव हुआ है|[8]

एसआरआइ, भारतीय उदाहरण- भारत में कृषि काफ़ी विरोधाभास के साथ कार्य करती है, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान होने के साथ, गेहूँ, चीनी, फल व सब्जियाँ उत्पादन में द्वितीय स्थान है परंतु इसके साथ- साथ भारत में कृषक मृत्यु दर भी सर्वाधिक है जो वास्तविक चिंता का विषय है और यह सब कृषि की दयनीय स्थिति के कारण है और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि उत्पादन में वृद्धि करने के पश्चात भी कृषकों के मुनाफ़े के प्रतिशत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है|[9]

आँकड़ों को देखा जाए तो पता चलेगा कि भारत में ही प्रत्येक वर्ष 210 अरब क्यूबिक मीटर ज़मीनी पानी निसकसित किया जाता है जो वैश्विक तुलनात्मक अध्ययन में सबसे अधिक है, वहीं यदि उपयुक्त जल की भी बात की जाए तो भारत में 60 प्रतिशत ऐसे जिले हैं जिनमें मात्रात्मक कम व कम गुणवत्ता वाला जल उपलब्ध है[10], अतः ऐसी स्थितियों में भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार की उत्पादन पद्दति की खास ज़रूरत है|

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी गाँधी के माध्यम से भी कुछ इसी प्रकार से स्वादेशिक ज्ञान कई देशीय समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया था, इससे कई और समाज भी

[1] Prasad, C. S, "System Of Rice Intensification In India: Innovation History And Institutional Challenges", Wwf-Dialogue Project At The International Crop Research Institute For Semi-Arid Tropics, Hyderabad, India, 2006, Pp-10.
[2] C Shambhu Prashad, "Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation", Ecology And Society, Vol.24, No.4, Dec-2016, Pp-3.
[3] Norman.Uphoff, "The System Of Rice Intensification As A System Of Agricultural Innovation", Vol.10, No-1, April-2008, Pp-27.
[4]. Ibid, (The System Of Rice Intensification As A System Of Agricultural Innovation), Pp-30.
[5] "Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology", Pp-18.
[6] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-4.
[7] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-4.
[8] Ibid, (The System Of Rice Intensification As A System Of Agricultural Innovation), Pp-28.
[9] Ibid.
[10] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-3.

प्रेरित हुए जैसे- बाबा आम्टे की महारोगी सेवा समिति, मानिभाई देसाई की भारतीय एग्रो इंडस्ट्री(पशुपालन), ऐला भट्ट का स्व-रोज़गार स्त्री संगठन आदि|[11]

विकास व सतत विकास- इस प्रकार से एसआरआइ व्यवस्था ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है परंतु इसके मार्ग में बहुत बाधाएँ भी हैं जो बाज़ारवादी शक्तियों से आती हैं| यह शक्तियाँ क्योंकि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बाज़ार में कुछ ऐसी तकनीकों को प्रस्तुत करती है जो ना तो कृषक वर्ग को लाभ पहुँचाते हैं और ना ही यह सब पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होता है, यहीं से इस प्रकार के उत्पादन के साथ विकास व सतत विकास का भी मुद्दा सामने आता है| इस प्रकार के वैज्ञानिक विकास से पर्यावरण शरणार्थी पैदा होते हैं जो युद्ध के तुलनात्मक भी काफ़ी अधिक हैं चिपको[12], अपिक्को आदि इसके उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं|

इस प्रकार के उत्पादन के पीछे केवल शहरीकरण, वैश्वीकरण व प्रगति की विचारधारा काम कर रही है|[13] आधुनिक रूप में जो विज्ञान काम कर रहा है वह अपने साथ हिंसात्मक व सत्तावादी रूप लेकर अपने चलता है जिसका प्रतिस्थापन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है[14], इस प्रकार के विज्ञान व बाज़ारवाद को पूंजीवाद व उदारवादी विचारधारा का काफ़ी समर्थन मिलता है जो कभी भी एसआरआइ जैसी व्यवस्थाओं को अपना प्रतिस्थापक नहीं बनने दे सकता|

इस पूर्ण उदारवादी, बाज़ारवादी प्रक्रम में रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे हरित गैसों, ओज़ोन परत, वैश्विक तापमान जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं, हरित क्रांति भी इसी का एक उदाहरण है जिसने उत्पादकता में तो वृद्धि की परंतु भूमि की उत्पादकता, उर्वरकता को क्षीण कर दिया, अतः इस प्रकार से यदि हमें विकास का ज़रिया परौसा जाएगा तो स्वाभाविक ही यह हमारे व हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, पर समस्या यह है कि इस ज्ञान की राजनीति में वैज्ञानिक समुदाय अपने आप को आगे रखना चाहता है, जो भविष्य के संकटों की ओर इशारा करता है|[15] अतः यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमें सतत विकास की आवश्यकता है जो एसआरआइ जैसी पद्दति से ही संभव है, जिसके लिए इस पश्चिमी ज्ञान के वजाय स्थानीय ज्ञान की ओर रूख़ अख्तियार करना होगा|[16],[17]

इस प्रकार का सतत विकास ग़रीब (स्थानीय) खोज़ से ही प्राप्त किया जा सकता है जिसमें ग़रीब को भी सहभागी बनाया जा सकता है|[18]

धान अधिक्य व्यवस्था व ज्ञान की राजनीति- 2004 में जब धान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया तो वैश्विक आधार पर एक अप्रत्यक्ष युद्ध सा छिड़ गया जो धान के ज्ञान को लेकर 'धान युद्ध' था|[19] धान का ज्ञान बाज़ार में एक नये प्रकार के ज्ञान की बात करता है वास्तव में इस प्रकार के ज्ञान को लाना व बाज़ार में प्रस्तुत करना इतना आसान नहीं है| देखा जाए तो राज्य व बाज़ार ऐसे अभिनेता हैं जो समाज से अपने लाभ का अंश व अपनी प्रभुसत्ता को समाप्त नहीं होने दे सकते, और इस प्रकार की व्यवस्था तो उनके अस्तित्व को ही ख़त्म कर देगी अतः उनका विरोध स्वाभाविक था और वह इस तीक्षणता में हुआ की इन शक्तियों के द्वारा इस प्रकार के स्तनीय ज्ञान को पनपने ही नहीं दिया व अपना स्वाभाविक विकास करता चला गया, यह सभी ज्ञान की राजनीति की कड़ियाँ हैं|[20] इस प्रकार के राज्य व बाज़ारवादी ताकतों के व्यवहार के चलते 1980 के दशक में यह ज्ञान की राजनीति का मुद्दा उफान पकड़ने लगा|[21]

किसी भी प्रकार के क्षेत्र में खोज़ कहीं से भी आ सकती है, इस प्रकार का वर्चस्व 20 वी शताब्दी तक विज्ञान व तक्निक्य चीज़ों तक ही सीमित था जिससे बारंबार उन्हीं लोगों को मुनाफ़ा प्राप्त हुआ है जो पूर्व से संपन्न थे|[22] वहीं इस प्रकार के उदारवाद ने अपने प्रस्तुतिकरण के साथ उत्तरदायित्वों को बदल दिया है वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका, दायित्वों व प्रभावों में भी कमी की है ये सब ज्ञान की राजनीति के रूप में कार्यरत है समाज पर बहुआयामी असर डाल रहे हैं|[23]

आरंभिक समय से ज्ञान की राजनीति इस प्रकार से अध्ययन का विषय नहीं थी यही कारण रहा की ज्ञान की राजनीति को इस नज़रिए से नहीं समझा पाया जा सका और जब समझा गया तो पूर्ण समाज संज्ञानात्मक न्याय की माँग करने लग गया| आज कम से कम यह संभव हो पाया है कि हम विविध ज्ञान को पहचान दे पाएँ हैं जैसे वैज्ञानिक व साधारण व्यक्ति(Layman), स्थानीय ज्ञान| परंतु वर्तमान वैज्ञानिक प्रभुत्वकारी व्यवस्था के कारण साधारण व्यक्ति को इतनी पहचान नहीं मिल पाती है इसी कारण इसे 'काल्पनिक साधारण व्यक्ति(Imagined Layman)' से संबोधित किया जाता है एक वह व्यक्ति संख्या में तो समान पहचान प्राप्त किए हुए है पर मात्रा में उसका प्रभाव कम है|[24] विज्ञान व साधारण व्यक्ति में जो संबंध पाया जाता है उनमें ज्ञान को अनदेखा करने वाला संबंध विद्यमान होता है| जिसके पीछे यह मानसिकता होती है कि साधारण व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तथ्यों व ज्ञान को रखने का कोई अधिकार व यह उनका व्यवसाय नहीं है|[25]

वन्लोक्युएरेन व बरेट ने इस विज्ञान व साधारण व्यक्ति के विवरण को कृषक समुदाय के नज़रिए से समझाया वे कहते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में अभियंता शोध पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वा कृषक वर्ग को अनदेखा किया जाता है वहीं कोशिश यह भी रहती है कि अनदेखा करने के साथ साथ उसके अस्तित्त्व का भी ख़ात्मा किया जाए, जिसकी वजह यह बिल्कुल भी नहीं है कि कृषकों को कम ज्ञान हो व अभियंताओं को ज़्यादा बल्कि यहाँ ज्ञान का निर्धारक तत्व लाभ व प्रभुत्व की राजनीति है|[26]

जब हम इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैये को देखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहिष्कार, दमन, भेदभाव केवल आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक रूपों में मात्र नहीं होते हैं आज देखा जाए तो वास्तव में इनका स्वरूप विस्तारित हो गया है जो अब अपने बहिष्करण के चित्र में संस्कृति व संज्ञानात्मक/ ज्ञानमीमंस के रंगों को भी लेकर साथ चलता है|[27]

वास्तव में देखा जाए तो एक वृहद कृषक समुदाय है जो ज्ञान को संजोए हुए है जिसे समय-समय पर वैज्ञानिकों से चुनौतियाँ मिलती रहती हैं जिसका एक बहुत बड़ा कारण संस्थाओं में कठोर श्रेणीबद्धता का होना है| वहीं यदि इस प्रकार की श्रेणीवद्धता को ख़त्म करना है तो नागरिक समाज के विस्तरित योगदान की आवश्यकता है|

यह विकास, बाज़ारवाद, पूंजीपत्योन्मुखी राज्य आदि त्रियेज(triage) व्यवस्था के आधार पर कार्य करते हैं जैसे चिकित्सकों के द्वारा छानन(filter) व्यवस्था का सहारा लिया जाता है जिसमें पहले उनका इलाज किया जाता है जिन आधारों पर उनके पास चिकित्सा सुविधा होती है, इसी प्रकार युद्ध की स्थिति में भी उन लोगों को ही पहले ठीक

---

[11] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-3.
[12] Shiva.Andana And Bandyopadhyay.J, "The Evolution, Structure, And Impact Of The Chipko Movement",Pp-141.
[13] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-13.
[14] Ibid, (Science, State And Violence: An Indian Critique Reconsidered), Pp-11.
[15] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-4.
[16] Prasad, C. S, "Rethinking Innovation And Development- Insight From The System Of Rice Intensification On India", Pp-2.
[17] Santos.Boaventura De Sousa, Nunes. Dodo Arriscado, Menses. Maria Paula, "Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference" In Boaventura De Sousa Santos, Another Knowledge Is Possible: Beyond Northern Epistemologies, Pp-Ix.
[18] Ibid, (Rethinking Innovation And Development- Insight From The System Of Rice Intensification On India), Pp-4.
[19] Ibid, (System Of Rice Intensification In India: Innovation History And Institutional Challenges), Pp-3.
[20] Ibid, (System Of Rice Intensification In India: Innovation History And Institutional Challenges), Pp-4.
[21] Ibid, (Science, State And Violence: An Indian Critique Reconsidered), Pp-2.
[22] Ibid, (System Of Rice Intensification In India: Innovation History And Institutional Challenges), Pp-7.
[23] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-14.
[24] Maranta. A M, Guggenheim. P Gisler, C. Pohl, "The Reality Of Expert And The Imagined Lay Person",Pp-150.
[25] Ibid, (The Reality Of Expert And The Imagined Lay Person), Pp-153.
[26] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-4.
[27] Ibid,(Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Ix.

किया जाता है जो तत्काल जाकर युद्ध में हिस्सा ले सकें, इस प्रकार से लोगों को छाँटा जाता है इसी प्रकार ज्ञान की राजनीति में ज़्यादा मुनाफ़ादायक पहलू को ध्यान में रखकर विविध कार्यों को किया जाता है जिसमें स्थानीय ज्ञान व महत्व को छान के किनारे कर दिया जाता है अतः समझा जा सकता है कि किस प्रकार से इस व्यवस्था से समाज का महत्वपूर्ण भाग बहिष्कृत कर दिया जाता है|[28] फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि सभी ज्ञान अपने आप को वैधता प्रदान कर शक्तिशाली बनना चाहते हैं, ऐसी शक्ति जो मानव व प्रकृति पर काबू कर सके[29], अर्थात ज्ञान का इस्तेमाल मात्र शक्ति एकत्रीकरण के लिए किया जाता है|

इस प्रकार के व्यवहार के कारण संज्ञानात्मक न्याय की माँग का मुद्दा उठता है जो सभी प्रकार के ज्ञान को संज्ञान में लेने की बात का पहलू रखते हैं|[30] बिना सामाजिक न्याय के वैश्विक सामाजिक न्याय भी संभव नहीं है[31] शिव विश्वनाथन ने 'कॉमन्स' का उदाहरण देते हुए बताया कि कॉमन की अवधारणा के साथ गावों के सभी लोग एकत्रित होकर विभिन्न प्रक्रम को संझाँ किया करते थे जो एक सामुदायिक पहल हुआ करती थी, विश्वनाथन कहते हैं कि इस प्रकार का कॉमन्स का विचार विकास के विस्तार के साथ-साथ सकूड़ता चला गया| यह तकनीकी के स्थानांतरण ने ही इस प्रकार के विकास व इसकी अवधारण को यहाँ प्रस्तुत किया है, उनके अनुसार ज्ञान का विविधिकरण व उसे मान्यता प्राप्त होना ही वास्तव में लोकतांत्रिकरण है जो समाज को संज्ञानात्मक न्याय तक पहुँचा पाएगा, साधारणतः विश्वनाथन इस विभेदीकरण को 'बौद्धिक भेदभाव (Intellectual Apartheid)' का नाम देते हैं|[32]

नारीवादी विचारक भी इस प्रकार के ज्ञान विभेदीकरण को तटस्थ करने की माँग करते है जो सदियों से पुरुष प्रभुत्व आधार पर काम कर रहा है, वह किसी भी नये प्रकार के विज्ञान की माँग नहीं करतीं हैं बल्कि विद्यमान विज्ञान में सहभागिता की बात करती हैं|[33] इसी प्रकार उत्तर-उपनिवेशवाद भी ज्ञान की वर्तमान संरचना पर प्रश्न उठाते हैं वे कहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में उपनिवेशी समाजों के ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता जो उपनिवेशवादी मानसिकता का ही प्रसार है, एक ऐसी मानसिकता जिसमें आज भी पूर्ण उपनिवेशों को पहचान के संकट का सामना करना पड़ रह है|[34] इसी प्रकार का ज्ञान विभाजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है जब ज्ञान के मामले में विश्व उत्तर-दक्षिण के रूप में बनता हुआ देखा जाता है, दक्षिण के देशों पर नव-उदारवादी(सेप) जैसी नीतियों को थोपा जाता है और इन्हीं आधारों पर विभिन्न परिवर्तनों को व्यावहारिकता प्रदान की जाती है जिस पर इन देशों को चलना एक मज़बूरी बन जाता है|[35] कॉक्स(Cox) व स्केचलर(Schechler) ने वर्तमान विद्यमान वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी इस प्रकार के ज्ञान के मध्य संघर्ष का एक साधन ही माना है|[36]

बहुसंस्कृतिवाद भी इस प्रकार के ज्ञान के बहुआयामी होने को स्वीकृत करता है|[37] गाँधी के द्वारा इस प्रकार के पश्चिमी ज्ञान को अहिंसक बताया है[38] वहीं वर्तमान विज्ञान को भी न्यायसिता के रूप में कार्य करना चाहिए जो दोनों ज्ञान का सहारा लेकर साथ चलता रहे|[39]

इस प्रकार के ज्ञान विभाजन में अन्य तत्व भी प्रभावकारी रहते हैं जैसे भारतीय सन्दर्भ में जाति काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभावकारी तत्व है जो आपके जन्म से पूर्व से ही आपके ज्ञान का दायरा निर्धारित कर देता है|[40] इस प्रकार के वातावरण में सेंटोस 'उपश्रित सार्वभौमिकवाद' की माँग करते हैं जो जिसमें ज्ञान की विविधता व इसको निचले स्तर तक मान्यता प्रदान की जा सकती हो|[41] बाकी यदि इस प्रकार से ही चलते रहे तो इस प्रकार का ज्ञान एक एकल संस्कृति को जन्म देगा जिससे स्थानीयता का ख़ात्मा होना तय है|[42]

अतः कहा जा सकता है कि अन्य ज्ञान की पहचान करना आवश्यक है, विविधता को संजों कर रखना होगा, सभी ज्ञान को संज्ञान में लेना होगा| इसका स्वरूप परिस्थितिकी की तरह होना चाहिए जिसनें अपने में सभी का समायोजन करके रखा हुआ है जिसमें प्रत्येक की अपनी पहचान है[43] इस प्रकार की विविधता से समस्याओं के समाधान के भी अनेक विकल्पों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं| वास्तव में देखा जाए तो पूंजीपतियों, बाज़ारवादियों के पास भी किसी प्रकार का तार्किक विमर्श नहीं है जो साधारण लोगों को अलग रखने की धरना को वैधता प्रदान करे, इसी कारण ज्ञान के लोकतांत्रिकरण की माँगें उठती हैं |[44] यह एक प्रकार से ग़रीब का विकास में योगदान का भी एक रूप है, जो अप्रत्यक्ष विकेंद्रीकरण को मजबूत करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ज़ुडा हुआ महसूस करेगा|[45] हिंद स्वराज लेख के माध्यम से भी इस प्रकार के 'स्वराज'(स्थानीय ज्ञान की महत्ता) पर ज़ोर दिया गया है|[46]

निसकर्षताः बताया जा सकता है कि इसके कुछ उपयोगी विकल्प हो सकते हैं जैसे सहभागी तकनीकी विकास, स्थानीय तकनीकी/ पद्दति प्रोत्साहन, कृषक केंद्रित दृष्टिकोण आदि|

इस प्रकार देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एसआरआइ विभिन्न पर्यावरणीय माहौल में कार्यरत रह सकता है, उत्पादन बड़ा सकता है, जल की लागत को कम व आय बड़ा सकता है जो और सुधारों की ओर कार्यरत भी है, परंतु कुछ स्वार्थी संस्थाओं के कारण समाज में इस प्रकार के ज्ञान को अनदेखा किया गया है और इसको अन्य जगहों पर विस्तरित होने से भी रोका गया| इस पूरी प्रक्रिया में हमे ज्ञान की राजनीति को समझना आवश्यक है जो राज्य, बाज़ार, पूंजीपतियों के द्वारा खेली जाती है जिसका पूर्ण प्रभाव ग़रीब कृषक वर्ग पर पड़ता है, नागरिक समाज भी इसके कारण नयी खोज़ से वंचित रह जाता है जो जीवनभर का व्यापक नुकसान साबित हो सकता है अतः इस प्रकार की ज्ञान की राजनीति को देश के हिट के लिए इस्तेमाल की जाती चाहिए ना की व्यक्तिगत लाभ हेतु|[47]

हमें स्थानीय संस्कृति सभ्यता को महत्व देना होगा, इसी कारण आनंदा कुमारस्वामी अपनी सभ्यता-संस्कृति की ओर पुनः देखने को कहते है, उनके अनुसार सर्वहारा वर्ग अपनी संस्कृति से अलग हो चुका है|[48] यदि संस्कृति को साथ लेकर नहीं चला जाएगा तो विज्ञान अपनी नकारात्मकता से संस्कृति की सकारात्मकता भी ख़त्म कर देगा|

---

[28] Ibid, (Science, State And Violence: An Indian Critique Reconsidered), Pp-5.
[29] Ibid, (Science, State And Violence: An Indian Critique Reconsidered), Pp-4.
[30] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-18.
[31] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Ix.
[32] Visvanathan. Shiv, "The Search For Cognitive Justice",Pp-2.
[33] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxxviii.
[34] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxxiii.
[35] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxxviii.
[36] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxxviii.
[37] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxii.
[38] Ibid.
[39] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-15.
[40] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-10-11.
[41] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxxix.
[42] Ibid, (Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference), Pp-Xxxix
[43] Visvanathan. Shiv, "The Search For Cognitive Justice",Pp-6.
[44] Ibid, (The Search For Cognitive Justice),Pp-8-9.
[45] Ibid, (Rethinking Innovation And Development- Insight From The System Of Rice Intensification On India), Pp-3.
[46] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-5.
[47] Icrisat,"System Of Rice Intensification- Experience Of Farmers In India", Pp-2.
[48] Ibid, (Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology), Pp-15.

संभव है इसके लिए एक लोक नीति की आवश्यकता है, जिसके साथ मात्र तकनीकी आयाम इसे वैधता प्रदान नहीं करवा पाएगा इसमें सामाजिक आयामों को भी जोड़ने की आवश्यकता है|[49]

वास्तव में हमें किसी कठोर सांविधानिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है बस प्रदत विविधता का समायोजन करने वाला कर्तव्य हमें निभाना होगा|[50]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Prasad, C. S, "System Of Rice Intensification In India: Innovation History And Institutional Challenges", Wwf-Dialogue Project At The International Crop Research Institute For Semi-Arid Tropics, Hyderabad, India, 2006, Link- File:///C:/Users/Inspiron/Downloads/2397-5230-1-Pb.Pdf
2. "Knowledge Swaraj: An Indian Manifesto On Science And Technology" December, 2009 Https://Steps-Centre.Org/Anewmanifesto/Manifesto_2010/Clusters/Cluster5/Indian_Manifesto.Pdf
3. Santos.Boaventura De Sousa, Nunes. Dodo Arriscado, Menses. Maria Paula, "Introduction: Opening Up The Canon Of Knowledge And Recognition Of Difference" In Boaventura De Sousa Santos, Another Knowledge Is Possible: Beyond Northern Epistemologies, (Verso Press: London, 2008), Link- Https://Knowledge4empowerment.Files.Wordpress.Com/2011/06/Sousa-Santos-Et-Al_Intro.Pdf
4. Prasad, C. S, "Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation", Ecology And Society, Vol.24, No.4, Dec-2016, Link- Https://Www.Ecologyandsociety.Org/Vol21/Iss4/Art7/
5. Norman.Uphoff, "The System Of Rice Intensification As A System Of Agricultural Innovation", Vol.10, No-1, April-2008, Link- Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/89ce/3cffb739ba73d82929ee2e4e986de61bc721.Pdf
6. Rajan. Ravi, "Science, State And Violence: An Indian Critique Reconsidered" In Science And Culture, Vol. 14, No. 3, Link- Https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/09505430500216866
7. Shiva.Andana And Bandyopadhyay.J, "The Evolution, Structure, And Impact Of The Chipko Movement", Mountain Research And Development, Vol. 6, No. 2 (May, 1986), Link- Http://Www.Indiaenvironmentportal.Org.In/Files/File/Chipko%20movement%20evolution.Pdf
8. Prasad, C. S, "Rethinking Innovation And Development-Insight From The System Of Rice Intensification On India", The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol. 12(2), 2007.
9. Scott. Bruce R, "The Political Economy Of Capitalism", Link- Http://Www.Hbs.Edu/Faculty/Publication%20files/07-037.Pdf
10. Said. Edward W "Orientalism", (New York: Vintage Book,1979), Link- Https://Monoskop.Org/Images/4/4e/Said_Edward_Orientalism_1979.Pdf
11. Maranta. A M, Guggenheim. P Gisler, C. Pohl, "The Reality Of Expert And The Imagined Lay Person", Acta Sociologica, Vol. 46, No. 2, Jun 2003, Link- Http://Journals.Sagepub.Com/Doi/Abs/10.1177/0001699303046002005
12. Visvanathan.Shiv, "The Search For Cognitive Justice" Http://Www.India-Seminar.Com/2009/597/597_Shiv_Visvanathan.Htm
13. Icrisat,"System Of Rice Intensification- Experience Of Farmers In India", Andhra Pradesh, Nov-2008, Link- Http://Www.Sri-India.Net/Documents/Farmersexperiences.Pdf

[49] Ibid, (Innovating At The Margins- The System Of Rice Intensification In India And Transformative Social Innovation), Pp-7.

[50] Rajan. Ravi, "Science, State And Violence: An Indian Critique Reconsidered" In Science And Culture, Pp-10.